International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 14 Issue 10, Oct 2024,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 UGC Approved Journal Number: 48887
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उच्च शिक्षा और उसकी समस्याएँ एवं सुझाव

डा० (श्रीमती) फरह जहीर
Dr Farah Zaheer, Asst prof., Department of Education
Dr. M.C. Saxena college of Education, Lucknow U.P

पृष्ठभूमि–
उच्च का शाब्दिक अर्थ है–ऊँची, श्रेष्ठ। सामान्य अर्थ में ऊँची शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो सामान्य शिक्षा से ऊंचे स्तर की हो। अंग्रेजी में इसे हायर एजूकेशन कहते हैं। भारत वर्ष में उच्च शिक्षा का प्रारम्भ वैदिक काल में हो चुकी थी। तब उच्च शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के बाद गुरुकुलीय शिक्षा से था। भारतवर्ष में आधुनिक उच्चशिक्षा का प्रारम्भ ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया था इसने सर्वप्रथम 1781 में कलकत्ता में ''कलकत्ता मदरसा की स्थापना को थी।'' वूड, 1854 में नन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालयो की स्थापना की। सही अर्थों में उच्चशिक्षा की शुरूआत यहीं से हुयी है।

भारत सरकार ने 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया। उसने उच्चशिक्षा के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को तीन वर्षीय कराने का सुझाव दिया। परन्तु उसे कुछ ही प्रान्तों ने स्वीकार किया। कोठारी आयोग ने देश भर के लिये 10+2+3 शिक्षा प्रणाण प्रस्तावित थी। वर्तमान में +2 के बाद उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती है। आज हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्वरूप, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के है।

उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही सामाजिक विकास कल्याण के विकास में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में, भारत को एक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहाँ सभी के लिये न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाइचारे का भाव हो एक ऐसे राष्ट्र के रूप विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे–जैसे हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगें, वैसे–वैसे भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेगें।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के उद्देश्य

- अच्छे चिन्तनशील, बहुमुखी प्रतिभावाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना।
- समग्र विकास के लिये पूर्व–विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों का एक, निर्धारण सेट शामिल करना ।
- सामाजिक स्तर पर शब्द को प्रबुद्ध सामाजिक रूप से जागरुक,, जानकार और साझा बनाना है जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके और अपनी समस्यायों को खोज कर लागू कर सके।

उच्च शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्यायें–

- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेस और नेतृत्व क्षमता का अभाव।
- संशात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणाम पर कम बल।
- गंभीर रूप से खंडित उच्चतर शौक्षिक परिस्थतिकी तंन्त्र।
- सीमित पहुँच विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है जो स्थानीय भाषा में पढ़ाते है।
- एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली।
- बहुत सारे संवृद्ध विश्वविद्यालय जिनके परिणाम स्वरूप अवर स्नातक शिक्षा के निम्न मानक।
- प्रशासन, वित्त एवं नियन्त्रण की समस्या।
- उच्चशिक्षा कि निजीकरण ।
- छात्र अनुशासनहीनता।
- शिक्षित बेरोजगारी।
- प्रतिभा पलायन की समस्या।

सुझाव

1. सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना।
3. उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना।
4. भारतीय भाषाओं और द्विमाषायी रूप से पढ़ जाने वाले आर्थिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना।
5. यह सुनिश्चित करना कि सभी सम्बन्धित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधायें व्हीलचेयर सुलभ और दिव्यांगजनो के अनुकूल हो।
6. वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिये ब्रिजकोर्स निर्मित करना।
7. ऐसे सभी विद्यार्थियो को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक भावनात्मक और अकादमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना।
8. भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना।
9. प्रवेश प्रक्रियायों को अधिक समावेशी बनाना।

उपरोक्त दर्शाये गये बिन्दुओं के अतिरिक्त–सभी नेतृत्व पदो और संस्थानों के प्रमुखों के लिये उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जाये जिन्होंने जदिल परिस्थितियों में प्रबंध करने के साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन किया हो। साथ ही सम्बद्ध मंत्रालयों के समन्वय एवं परामर्श करके केन्द्र एवं राज्य दोनो स्तरो पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ का गठन करके उद्देश्यों को चरणवद्ध और स्पष्ट से प्राप्त करने के लिए सिद्धान्तो के अनुसार योजना लागू करनी चाहिये। संकाय, सदस्यों को स्वीकृति फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्य पुस्तकों के चयन तथा असाइनमेन्ट और ऑकलन और प्रक्रियायों को निर्मित करने के साथ ही अपने स्वयं के पाठयक्रम सम्बधी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतन्यता दी जानी चाहिये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से, सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक जीवन्त और न्यायसंगत

ज्ञान समाज में बदलने के लिये प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी होगी।

उपसंहार एवं निष्कर्ष

संक्षेप में कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्या है जैसे निजीकरण की समस्या उन्नयन की समस्या, अनुशासनहीनता, क्षय आक्रोश और मूल्यांकन पद्धति में सुधार आदि की समस्या। किसी भी छात्र समस्या को हल करने के लिये दो साधन है। एक वित्तीय संसाधन और दूसरा कार्यरत व्यक्तियों की ईमानदारी यदि इन समस्यायों को दूर कर दिया जाए तो समझिये पूरा जंग जीत लिया है।

वर्तमान में 2020 नयी शिक्षा नीति लागू की जारी जा रही है इसमें उच्च शिक्षा के प्रभावी निजीकरण उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देते समय यह सुनिश्चित किया जाए की कि शिक्षा केवल ख्याति प्राप्त संस्थानो के हवाले हो जिससे कि उनमें वाणिज्यिक तौर पर कमाई का साधन बनने की प्रवृत्ति न पनपे।

यही कुछ जा सकता है कि आज हमारे परम्परागत संस्थान यदि दिशा हीनता, नियोजनहीनता, पुरातन पाठ्यक्रम, गुटबन्दी, नियुक्ति में पक्षपात तथा वित्तीय संसाधनो के दुरूपयोग आदि समस्यायों से ग्रस्त है तो दूसरी निजी संस्थान उद्योगों की भाँति, निवेश के बदले धन प्राप्ति, व्यापार और मुनाफे की भावना से संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में दोष विद्यमान है जिनको दूर करके ही उच्च शिक्षा को सभी दिशा प्रदान की जा सकती है।

संदर्भ

1. National Education Policy 2020
2. Vaishnav, A, (2020) Report summary National Education Policy 2020
3. Bhatiya shiksha shodh Sansthan Niralanagar Lucknow Journal - 2020,2021,
4. Development of Indian Education R- Lal Book Dept. meerut (Raman Biharilal & sumita palod,
5. Dainik Jagran, Amar ujala News Paper Edition- 2024, 2023